an>

Title: Regarding the plight of sugarcane growers in Western Uttar Pradesh.

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): माननीय सभापति जी, पश्चिम उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों की बहुत बुरी हालत है। आप स्वयं पश्चिम उत्तर प्रदेश से आते हैं। आपको सभी चीज़ों की जानकारी है। वहां गन्ना किसानों को अभी तक पिछले वर्ष का भुगतान नहीं हुआ है। 19 नवंबर को प्रदेश के संबंधित मंत्री ने बताया कि अभी तक किसानों को 1445 करोड़ रुपये के भुगतान का बकाया है। इसका असर यह हो रहा है कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं। बागपत में, बिजनौर में, सहारनपुर में आत्महत्याएं हुई हैं। टिकरी, बागपत का एक उदाहरण तो बहुत ही हृदय विदारक है। उसने 80,000 रुपये का कर्ज़ भैंस खरीदने के लिए लिया था और 1,53,000 रुपये उसका गन्ने का बकाया था। उस पर बच्चों की स्कूल की फीस देने का दबाव था। वह नहीं कर पाया और पूरे देश का पेट भरने वाला किसान हिम्मत हार कर आत्महत्या कर बैठा। इस प्रकार की घटनाएं वहां पर हो रही हैं।

उन्हें गन्ने का दाम नहीं मिल रहा है। पिछली बार सरकार ने तय किया कि 280 रुपये में से 20 रुपये उन्हें बाद में मिलेंगे। इस बार 240 रुपये किया। उस बीस रुपये का आज तक पता नहीं है। जैसा मैंने पहले ही कहा कि सरकार खुद ही स्वीकार कर रही है कि उनका भुगतान अभी बाकी है। किसानों की लागत 272 रुपये से 290 रुपये के बीच में है, लेकिन वहां पर उनके गन्ने का ठीक दाम नहीं मिल पा रहा है। इसी के साथ, मिलें नहीं चल रही हैं। अभी तक पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर जो सोलह मिलें हैं, उनमें से तीन मिलें अभी तक नहीं चलीं हैं। मेरे पास जो खबर है, उसके अनुसार पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग 119 मिलों में से आधी मिलें अभी नहीं चलीं हैं। इसका परिणाम यह हो रहा है कि किसान अपने गन्ने का डिस्ट्रेस सेल के अंदर देने को मज़बूर हैं और खेत खाली न होने के कारण उसका असर गेहूं की फसल के ऊपर भी पड़ने वाला है।

महोदय, हालत यह है कि गन्ने का भुगतान न मिलने से वह बिजली का भुगतान नहीं कर पाता। यदि 30औ से अधिक लोगों ने बिजली का भुगतान नहीं किया है तो उस पूरे गांव की बिजली काट दी जाती है। यह इतना दुःखद है और वहां की सरकार हमेशा किसानों के खिलाफ़ दिखाई देती है और चीनी मिलों के साथ दिखाई देती है। प्रदेश की मंडी में प्रवेश-शुल्क में उसने दो प्रतिशत की छूट दी है। उसने उनका 6.70 रुपये प्रति क्विंटल विकास शुल्क माफ किया है, लेवी समाप्त की है। सरकार भी मिलों के साथ दिखाई देती है, किसानों के साथ खड़ी दिखाई नहीं देती है।

सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से निवेदन है कि इसमें हस्तक्षेप करे। प्रतिवर्ष वहां का जो गन्ना किसान बर्बाद होता है, उसको कुछ राहत मिले, उसका कोई हाथ पकड़ ले, यह मेरा आपसे निवेदन है।

सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं पुन: आपका बहुत-बहुत आभारी हूं।